भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1095

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

एनएपीएस के अंतर्गत नामांकित प्रशिक्षु

1095. श्री सी. एन. अन्नादुरई: श्री नवसकनी के.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत नामांकित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत वित्तीय वर्ष में एनएपीएस के अंतर्गत नियोक्ताओं और प्रशिक्षुओं दोनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना में भाग लेने के लिए लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि एनएपीएस के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कौशल विकास के अपेक्षित मानकों को पूरा करता है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उद्योग, निकायों या शैक्षणिक संस्थानों के साथ कोई साझेदारी की गई है;

(च) उक्त योजना में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) गत वित्तीय वर्ष में उक्त योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के कितने प्रशिक्षु लाभान्वित हुए?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) अगस्त 2016 में शुरू की गई थी और इसे वित्त वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए बढ़ाया गया था। एनएपीएस-2 के तहत, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वजीफा सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 (31.01.2025 तक) में अखिल भारतीय स्तर पर लगे प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 8,22,196 है। एनएपीएस-2 के तहत, पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, (i) प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत दावा प्रतिपूर्ति के लिए योजना के पिछले संस्करण के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों और (ii) प्रशिक्षुओं को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किए गए वजीफे के सरकारी हिस्से के लिए निधि जारी की गई थी। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी किए गए फंड का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	संवितरित राशि		
	दावा पुनर्भुगतान	डीबीटी	कुल
2023-24	258.45	335.84	594.29

(ग) एनएपीएस-2 के तहत, डीबीटी के माध्यम से शिक्षुओं को वजीफे के सरकारी हिस्से के रूप में योजना के तहत प्रोत्साहन में छोटे और मध्यम आकार के प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित प्रशिक्षु भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 (31.01.2025 तक) तक योजना के तहत लाभान्वित होने वाले छोटे और मध्यम आकार के प्रतिष्ठानों की संख्या नीचे दी गई है:

प्रतिष्ठान श्रेणी	नियोजित शिक्षु	प्रतिष्ठानों की संख्या
मध्यम	6,90,405	11,693
छोटा	1,78,469	10,627

स्रोत: www.apprenticeshipindia.gov.in

(घ) और (ङ) शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत, अपेक्षित मानकों में आम तौर पर ये शामिल हैं: न्यूनतम आयु आवश्यकताएँ, व्यापार के आधार पर विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताएँ, शारीरिक फिटनेस मानक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों घटकों के साथ एक परिभाषित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नियोक्ता और शिक्षु के बीच शिक्षुता का अनुबंध, निर्धारित प्रशिक्षण अवधि और कार्यस्थल के भीतर सुरक्षा नियमों का पालन; ये सभी आमतौर पर प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों द्वारा शासित होते हैं जो प्रशिक्षुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करते हैं। 2014 के संशोधन में शिक्षु अधिनियम ने नियोक्ताओं को विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अपने स्वयं के शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया, जिन्हें "वैकल्पिक व्यापार" के रूप में जाना जाता है। सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) जो उद्योग-नेतृत्व वाली संस्थाएँ हैं, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं और कार्यबल को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के साथ उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को संरेखित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परिषदें कार्यबल द्वारा आवश्यक कौशल की पहचान करने, प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एसएससी और प्रतिष्ठानों के लगभग 700 वैकल्पिक ट्रेडों ने प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को आकर्षित किया है।

(च) और (छ) सुधार (सुविधा और प्रक्रिया सरलीकरण), जागरूकता कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं के साथ निरंतर जुड़ाव, शिक्षुता मेला और छात्रों और प्रतिष्ठानों के बीच शिक्षुता प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक पहुंच के माध्यम से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पर मंत्रालय द्वारा दिया गया जोर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ये सभी प्रयास ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं को शामिल करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए, 11 लाख निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले, देश भर में शिक्षुता पोर्टल के माध्यम से 9.32 लाख शिक्षुओं को शामिल किया गया है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं का विवरण शिक्षुता पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है।

***